GIRIDHAR GOMANGO) : (a) to (c) No programme named, 'New Package Programme' is being implemented, or funded by the Planning Commission in the State of Gujarat. Therefore, the question of identification of development blocks or activities under the programme or allocation of funds under it does not arise.

निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2476. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 6-12-93 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 385 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है कि जिनकी लागत में वृद्धि हो गई है तथा उनके संबद्ध मंत्रालयों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने में हो रहे असाधारण विलम्ब को देखते हुए सरकार एक पृथक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 385 दिनांक 6-12-93 के संदर्भ में, 109 परियोजनाओं में मूल लागत के मुकाबले 50% से अधिक लागत वृद्धि हुई है। परियोजनाओं की संख्या और संबंधित क्रमशः मंत्रालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

@2476-ए. **श्री सोमपाल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद बैठकें किस-किस तारीख को हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) उक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

विवरण

(क) और (ख) इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की दो बैठकें, एक 5 अप्रैल, 1993 को तथा दूसरी 18 सितम्बर, 1993 को आयोजित की गई। अप्रैल, 1993 को आयोजित बैठक में एनडीसी की मितव्ययता संबंधी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।

समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का आमतौर पर समर्थन करते हुए परिषद ने योजना आयोग को इनकी सिफारिशों पर व्यापक विचार विमर्श करने का निदेश दिया। विद्युत संबंधी एक एनडीसी समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के अनुसार निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की गई :--

(i) योजना आयोग ने अप्रैल—जून 1993 के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों तथा नैशनल काउंसिल (जे सी एम) स्टाफ साइड केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ सहित व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श किया। इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद को 18 सितम्बर, 1993 को

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3025, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 से स्थानान्तरित।